और दक्षता में अवश्य अन्तर होता है और उनसे इसी हिसाब से काम लिया भी जाता है, इस को देखते हुए दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों की तरक्की का अलग-अलग प्रतिशत निश्चित किया जाएगा या नहीं ? सरकार यह निर्णय ले भी सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में भी यह कहा गया है कि एक सी ड्यूटी अथवा कार्य होते हुए भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तरक्की के नियम बनाए जा सकते हैं । इस बारे में आप की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सिकन्दर बख्त : 1972 में जो रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे, उन में यह था--

Diploma in Engineering or equivalent thereof or any other higher qualification.

इस में डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरी मिलने की ओपनिंग्स बहुत कम है । अगर तरक्की देने के लिए उन की परसेन्टेज कम कर दें, तो इस में डिप्लोमा होल्डर्स के साथ नाइंसाफी होगा, जोकि मुनासिब बात नहीं होगी ।

श्री लाल जी भाई : इस में बहुत गोलमाल होगा है । सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उस के बारे में नहीं बताया ।

MR. SPEAKER: We go to the next question—Qn. 472.

Damage caused to F.C.I. godowns in Andhra Pradesh

*472. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the extent of damage caused to the godowns of the Food Corporation of India located in the areas in Andhra Pradesh hit by recent cyclone;

(b) the loss of foodgrain suffered on this account; and

(c) whether there is a proposal to construct godowns by the F.C.I. away from the cyclone prone areas and if so, the particulars thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) FCI has reported that some roofing sheets were blown off and some light fittings damaged at some godowns situated in the areas in Andhra Pradesh hit by recent cyclone. The cost of repairs is estimated to be Rs. 40,000.

(b) A quantity of 35,000 metric tonnes of foodgrains is reported to have been affected. The salvaging of affected stocks is in progress and the actual quantity damaged will be known after the salvaging of the affected stocks is completed.

(c) No, Sir. In selecting locations for foodstorage godowns a number of considerations such as potential of procurement, needs of public distribution system, availability of land, suitability from railways point of view are taken into account.

श्री अनन्त दवे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने ऐसा बताया है कि ?

"A quantity of 35,000 metric tonnes of foodgrains is reported to have been affected."

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी कीमत का अनाज इफेक्टेड हुआ है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि अभी सैलवेज का काम हो रहा है और 35 हजार टन एफेक्टेड है लेकिन इसमें कितना खराब हो गया है जोकि ह्यूमन कन्जम्पशन के लिए सूटेबल नहीं रह गया है । उसका अनुमान है कि 5050 टन होगा । यह अनाज खाने के लिए नहीं दिया

जाता है। इसमें सवा करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा, ऐसा अनुमान है।

श्री अन्नत दवे : जो अनाज खराब हो गया है, उसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा ? इसके बारे में सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : हमारे यहां यह तरीका है कि उसकी जांच होती है। अगर वह ह्यूमन कंजम्सन के लिए फिट नहीं होता है तो उसे खाने के लिए नहीं दिया जाता है। इसके बारे में नियम बने हुए हैं। इसके डिस्पोजल के बारे में स्टेट गवर्नमेंट से कहा जाता है और उन्हें आफर किया जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है जो अनाज खाने योग्य नहीं है वह इन्सानों तक न पहुंचे।

श्री तेज प्रताप सिंह : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि ये जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार चाहे गल्ला खराब क्यों न हो जाए लेकिन उसे आसपास के लोगों को नहीं दिया जाता है, चाहे उनकी क्रय शक्ति हो या न हो, क्या यह गल्ला ऐसे लोगों को दिया जायेगा जो साइक्लोन से पीड़ित हैं और जिनके पास खाने के लिए नहीं है ? क्या ऐसा गल्ला जो खाने के लायक है, इन भूख से भीड़ित लोगों को दे दिया जाएगा ? क्या इसीलिए नियम में भी परिवर्तन किया जाएगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह : साइक्लोन से पीड़ित लोगों को बहुत अच्छा गल्ला दिया जा रहा है। उनके लिए गल्ले की कमी नहीं है। लेकिन जो गल्ला इन्सान के खाने लायक नहीं है, वह गल्ला हम जरूर इन्सान के हाथों में पहुंचने से रोकना चाहते हैं।

SHRI M. S. SANJEEVI RAO: Sir, in view of the great devastation which has been caused in Andhra Pradesh, and also taking into consideration the fact that there are many factories which have collapsed which has caused heavy unemployment problem there, will the hon. Minister consider the construction of more godowns in that area so that this problem can be solved to some extent? As he is aware, it is a rice-bowl, not only of the South, but of the entire country. Will the construction of more godowns be undertaken there?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Large scale construction of godowns is already in hand and that area will certainly receive its due share of consideration and there is no doubt about it.

छोटे और सीमान्त किसानों के लिये सामुदायिक नलकूप

*473. **श्री रुद्रसेन चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों के उत्थान के लिए छोटे सामुदायिक नलकूप लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). Yes Sir. The installation of small community tubewells wherever feasible are being taken up under the normal minor irrigation programmes implemented through the State Plan Resources and institutional investment. In addition, special emphasis is being laid on construction of community wells under the Central Sector Programmes such as Small Farmers Development Agency, Drought Prone Area Programme, Integrated Tribal Development Programme, Command Area Development Programme, etc. Specially higher subsidy of 50 per cent is being provided for the community wells under these programmes.